



2024:सीजीएचसी:42578

1

एफआर

## उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

आदेश आरक्षित दिनांक - 14.10.2024

आदेश दिनांक- 25.10.2024

विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक- 6597/2024

- 1- दिलीप पांडे पुत्र छोटे लाल पांडे, उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी मकान क्रमांक पी-3 ए/676, सेक्टर 27, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

...आवेदक

**बनाम**

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा डीएसपी, ईओडब्ल्यू/एसीबी रायपुर,

...अनावेदक

आवेदक की ओर से

: श्री यतिन ओझा, सीनियर. अधिवक्ता श्री शिशिर प्रकाश,  
श्री अनुराग आर.राठौर, एवं श्री मनय ठाकुर, अधिवक्ता।

अनावेदक/राज्य की ओर से

: डॉ. सौरभ कुमार पांडे, उप. महाधिवक्ता ।

(माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा)

सी ए वी आदेश

1. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ('BNSS') की धारा 483 के तहत दायर किया गया है, जिसमें आवेदक अपराध संख्या 4/2024 में नियमित जमानत की मांग कर रहा है, जो कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), रायपुर द्वारा 17.01.2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और 34 के तहत पंजीकृत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि ईओडब्ल्यू को प्रवर्तन निदेशालय से 11.07.2023 को एक संचार प्राप्त हुआ और उचित सत्यापन के बाद, भ्रष्टाचार निवारण



अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 तथा IPC की धारा 420, 467, 471 और 120(ब) के तहत एक संज्ञेय अपराध का प्राथमिक रूप से पता चला और प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपराध संख्या 04/2024 के तहत पंजीकृत किया गया।

3. आवेदक का मामला यह है कि आवेदक पिछले पांच वर्षों से प्रिज्म होलोग्राफी में कार्यरत है। प्रारंभ में उसे 25,000/- रुपये के वेतन पर नियुक्त किया गया था और धीरे-धीरे यह बढ़कर 50,000/- रुपये हो गया। नियोक्ता/कंपनी ने आवेदक को डेटा को बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए नियुक्त किया है। आवेदक को 09.07.2024 को एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर, जिला रायपुर की पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 तथा IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और 34 के तहत आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने M/s. प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर इकाई में पर्यवेक्षक/ऑपरेटर/उत्पादन प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए सहयोगी की भूमिका निभाई और नकली होलोग्राम प्रदान करने में सहायता की, जिसके कारण अवैध शराब बेची गई और इसलिए, 26.09.2024 को वर्तमान आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि उप निदेशक, हेमंत गहलोत के एक गोपनीय पत्र ECIR/RPZO/11/2022/279 दिनांक 11.07.2023 के आधार पर, उत्तरवादी द्वारा सिंडिकेट के अवैध आय के प्रमुख स्रोतों में से एक अनील टुटेजा के साथ अनवर देबर, अरुणपति त्रिपाठी, MD CSMCL और उनके सहयोगियों विकास अग्रवाल @ सुब्बू, अरविंद सिंह, श्री संजय दीवान और देशी शराब के आसवक, आबकारी अधिकारी आदि के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिन्होंने देशी शराब के आसवकों M/s. CG डिस्टिलरी लिमिटेड, M/s. भाटिया वाइन्स मर्चेन्ट प्राइवेट लिमिटेड और वेलकम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से कमीशन लिया और इसे भाग अ अपराध के रूप में वर्णित किया गया है।

4. इसके अलावा, अभियोजन ने अपराध को भाग ब अपराध में विभाजित किया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त नामित व्यक्तियों ने शराब बेचने के लिए



एक समानांतर तंत्र बनाया है। शराब को सरकारी दुकानों से ऑफ द रिकॉर्ड निर्मित और बेचा गया है, जिसमें आसवक मालिक, बोतल आपूर्ति एजेंसी और 2019 से 2023 तक नकली होलोग्राम बनाने में सहायता की गई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रिज्म होलोग्राम एंड सिक्क्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विधु गुप्ता ने रायपुर में अपने कार्यालय के माध्यम से नकली होलोग्राम की आपूर्ति की है, जिसमें वर्तमान आवेदक प्रभारी के रूप में कार्यरत था और राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश में शामिल था और पूर्व-मुद्रित होलोग्राम के बारे में जानकारी रखता था और नकली होलोग्राम के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग और अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भाग C में यह आरोप लगाया गया है कि आसवकों को छत्तीसगढ़ राज्य में काम करने की अनुमति देने के लिए वार्षिक कमीशन दिया गया था।

5. ईओडब्ल्यू ने आयकर विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी और डेटा का विश्लेषण किया है, जिसके आधार पर यह स्थापित किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग में अवैध कमीशन कमाने के लिए सिंडिकेट द्वारा एक सुनियोजित साजिश को अंजाम दिया गया था। तदनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2024 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच के अनुसार, शराब को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात् देशी शराब (CL) और भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL)। देशी शराब छत्तीसगढ़ राज्य में तीन आसवनशालाओं के माध्यम से उत्पादित की जाती है, अर्थात् i) M/s. छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ii) M/s. भाटिया वाइन्स एंड मर्चेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और iii) M/s. वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड।

6. आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यतीन ओझा ने तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक को गलत तरीके से फंसाया गया है और उसका कोई इरादा नहीं था और न ही मुख्य आरोपी के साथ कोई आपराधिक साजिश थी। आवेदक को ईओडब्ल्यू, रायपुर द्वारा



पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2024 में आरोपी बनाया गया है। निस्संदेह, आवेदक एक वेतनभोगी कर्मचारी है और उत्तर प्रदेश का निवासी है और उसे यूपी प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा सीजी प्रथम सूचना रिपोर्ट में गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था। यह तर्क किया गया है कि आरोप पत्र के अनुसार, आवेदक केवल मालिक के निर्देशों पर कार्य कर रहा था और उसे कोई जानकारी नहीं थी। नकली होलोग्राम नोएडा, यूपी से भेजे जाते थे, जहां से यह रायपुर और आगे आसवनशालाओं को भेजा जाता था। आवेदक इसे स्थानांतरित करता था और उन व्यक्तियों को सूचित करता था जहां इसे भेजा जाना था और कभी-कभी वह व्यक्तिगत रूप से जाकर मालिक विधु गुप्ता के आदेशानुसार वितरण करता था। इस जानकारी के आधार पर, 29.07.2024 के छह महीने बाद 17.01.2024 को ईओडब्ल्यू द्वारा एक अपराध पंजीकृत किया गया। 17 जनवरी 2024 से, आवेदक को न तो बुलाया गया और न ही उसका बयान दर्ज किया गया, लेकिन जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 12.04.2024 को ECIR को रद्द किया, आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आवेदक ने उक्त मामले में जमानत याचिका दायर की, आवेदक को 12.04.2024 को दूसरे ECIR के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आवेदक 15 फरवरी 2024 से हिरासत में है।

7. इस ECIR को चुनौती दी गई और ईओडब्ल्यू द्वारा पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अनुमत माना। डिवीजन बेंच के उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी के अनुसार मुख्य व्यक्ति श्री निरंजन दास हैं, जो मामले के प्रमुख थे और छत्तीसगढ़ सरकार के आयुक्त (आबकारी) थे। उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। यह तथ्य है कि 8 मई 2024 से लेकर खारिज होने की तारीख तक और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने की तारीख तक, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री टुटेजा पिता



और पुत्र दोनों के मामले में पहला आदेश पारित किया था। पुत्र को सुरक्षा प्रदान की गई क्योंकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था, उसे 8 मई 2024 के बयान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। यह तथ्य बना हुआ है कि प्रमुख आरोपी, चाहे वे निजी हों या सरकारी, विभाग के सर्वोच्च व्यक्ति आबकारी आयुक्त और प्रिज्म के निदेशक दोनों स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और निरंजन दास के अधीन काम करने वाले व्यक्ति आज जमानत की मांग कर रहे हैं, मुख्य रूप से लंबे समय तक हिरासत में रहने के आधार पर। उन्होंने \*\*श्री अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, आपराधिक अपील संख्या 2493/2024\*\* के निर्णय पर अपना भरोसा जताया है, जो इस प्रकार है:--

"3.2. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17.08.2022 को IPC की धारा 120-ब के साथ धारा 477 अ और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या RCO032022A 0053 दर्ज की। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ अनियमितताओं, जालसाजी, अनुचित लाभ और साजिश का आरोप लगाया गया था, जो GNCTD के भीतर जिम्मेदार पदों पर आसीन थे, जिन्होंने 2021-2022 के लिए आबकारी नीति (आबकारी पॉलिसी) को तैयार करने और लागू करने में भूमिका निभाई। हालांकि, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल नहीं था।"

7. उन्होंने निर्णय के पैरा 14 का भी उल्लेख किया है, जिसमें यह कहा गया है:

"14. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और पक्षों द्वारा की गई व्यापक दलीलों पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए हैं:

i) क्या आवेदक की गिरफ्तारी में कोई अवैधता थी? यदि हां, तो क्या आवेदक को औपचारिक जमानत आवेदन के अभाव में तुरंत रिहा किया जाना चाहिए?

ii) क्या आवेदक, अपनी वैध गिरफ्तारी के बावजूद, नियमित जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है?

iii) क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में ऐसा निर्णायक परिवर्तन है कि एक आरोपी को नियमित जमानत के लिए मामला बनाने के लिए विचारण कोर्ट के पास भेजा जाएगा?"



8. निर्णय के पैरा 35 में यह कहा गया है:

"38. भारत में जमानत कानून के विकास से पता चलता है कि जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने के बोझ से संबंधित है, जो यह मांग करते हैं कि जमानत का विकसित कानून सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। [4] इस सिद्धांत को और विस्तारित किया गया है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि एक आरोपी व्यक्ति का लंबे समय तक हिरासत में रहना, विचारण लंबित होने के कारण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण वंचन है। इस न्यायालय ने भारत सरकार बनाम के.ए. नजीब में इस सिद्धांत को अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के प्रावधानों के तहत भी विस्तारित किया है, भले ही उस अधिनियम की धारा 43-D(5) में निहित वैधानिक प्रतिबंध हो, यह स्थापित करते हुए कि जमानत देने के खिलाफ विधायी नीति तब पिघल जाएगी जब विचारण के उचित समय में पूरा होने की संभावना नहीं होगी। [5] न्यायालय आमतौर पर 'स्वतंत्रता' के पक्ष में झुकेंगे, एक अंडर विचारण के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाएंगे, सिवाय इसके कि जब ऐसे व्यक्ति की रिहाई से सामाजिक आकांक्षाएं टूटने, विचारण को पटरी से उतारने या आपराधिक न्याय प्रणाली को बदनाम करने की संभावना हो, जो कानून के शासन का अभिन्न अंग है।

[4] गुडिकांति नरसिम्हलु बनाम पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (1978) 1 SCC 240

[5] भारत सरकार बनाम के.ए. नजीब, AIR 2021 SC 712

39. इन कार्यवाहियों के दौरान यह प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 17.08.2022 को पंजीकृत की गई थी और तब से, आरोप पत्र के साथ चार पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। सबसे हालिया पूरक आरोप पत्र 29.07.2024 को दाखिल किया गया था और हमें सूचित किया गया है कि विचारण कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है। इसके अलावा, 17 आरोपी व्यक्तियों को नामित किया गया है, 224 व्यक्तियों को गवाह के रूप में पहचाना गया है और व्यापक दस्तावेजीकरण, भौतिक और डिजिटल दोनों, प्रस्तुत किया गया है। ये कारक सुझाव देते हैं कि विचारण का पूरा होना निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है।



40. हमारे विचार में, हालांकि आवेदक की गिरफ्तारी की प्रक्रिया वैधता और अनुपालन के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है, विचारण लंबित होने के कारण लंबे समय तक हिरासत में रहना स्थापित कानूनी सिद्धांतों और आवेदक के स्वतंत्रता के अधिकार, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है, का उल्लंघन करेगा। आवेदक को इस न्यायालय द्वारा 10.05.2024 और 12.07.2024 को ED मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी, जो एक ही तथ्यों से उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा, सीबीआई और ED मामलों में कई सह-आरोपियों को भी विचारण कोर्ट, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा अलग-अलग कार्यवाहियों में जमानत प्रदान की गई है।

41. जहां तक विचारण के परिणाम को प्रभावित करने की आवेदक की आशंका का संबंध है, ऐसा लगता है कि सीबीआई के निपटान के लिए सभी सबूत और सामग्री पहले से ही उनके कब्जे में है, जो आवेदक द्वारा छेड़छाड़ की संभावना को नकारता है। इसी तरह, आवेदक की स्थिति और समाज में उसकी जड़ों को देखते हुए, उसके देश से भागने की आशंका को मान्य करने का कोई वैध कारण नहीं लगता है। किसी भी स्थिति में, सीबीआई की आशंकाओं को दूर करने के लिए, हम सख्त जमानत शर्तें लगा सकते हैं। जहां तक आवेदक द्वारा गवाहों को प्रभावित करने का संबंध है, इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी किसी भी घटना में, यह जमानत की रियायत का दुरुपयोग होगा और आवश्यक परिणाम होंगे।

42. इसलिए इन विशेष परिस्थितियों के प्रकाश में और उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदक जमानत देने के लिए आवश्यक तीन शर्तों को पूरा करता है। हम तदनुसार आदेश देते हैं।"

9. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयान द्वारा निर्णय के पैरा 22 में यह कहा है:

"22. जहां तक सीबीआई द्वारा आवेदक की गिरफ्तारी का संबंध है, यह उतने सवाल उठाता है जितने इसके जवाब देने का प्रयास करता है। जैसा कि पहले



ही उल्लेख किया गया है, सीबीआई मामला 17.08.2022 को पंजीकृत किया गया था। ED द्वारा 21.03.2024 को आवेदक की गिरफ्तारी तक, सीबीआई ने आवेदक को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की, हालांकि उसने लगभग एक साल पहले 16.04.2023 को उससे पूछताछ की थी। ऐसा लगता है कि केवल तब विद्वान विशेष न्यायाधीश ने 20.06.2024 को ED मामले में आवेदक को नियमित जमानत प्रदान की (जिसे उच्च न्यायालय ने 21.06.2024 को मौखिक उल्लेख पर रोक दिया), सीबीआई सक्रिय हो गई और आवेदक की हिरासत की मांग की, जिसे विद्वान विशेष न्यायाधीश ने 26.06.2024 को स्वीकार कर लिया। 26.06.2024 को सीबीआई द्वारा उसकी गिरफ्तारी के दिन भी आवेदक को सीबीआई द्वारा आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। केवल सीबीआई द्वारा 29.07.2024 को दाखिल किए गए अंतिम आरोप पत्र में, आवेदक को आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

23. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीबीआई ने 17.08.2022 से 26.06.2024 तक लगभग 22 महीनों तक आवेदक को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। यह केवल तब हुआ जब विद्वान विशेष न्यायाधीश न्यायाधीश ने ED मामले में आवेदक को नियमित जमानत प्रदान की, सीबीआई ने अपना तंत्र सक्रिय किया और आवेदक को हिरासत में ले लिया। सीबीआई की ओर से इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न लगाती है; बल्कि गिरफ्तारी पर ही। 22 महीनों तक, सीबीआई आवेदक को गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन जब विद्वान विशेष न्यायाधीश ED मामले में आवेदक को नियमित जमानत प्रदान करता है, तो सीबीआई उसकी हिरासत की मांग करती है। परिस्थितियों में, यह दृष्टिकोण लिया जा सकता है कि सीबीआई द्वारा इस तरह की गिरफ्तारी शायद केवल ED मामले में आवेदक को दी गई जमानत को विफल करने के लिए की गई थी।

24. जहां तक गिरफ्तारी के आधारों का संबंध है, मेरा मानना है कि वे आवेदक की गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए आवश्यकता की कसौटी को पूरा नहीं करते हैं और अब जब आवेदक हिरासत के बाद जमानत की मांग कर रहा है, तो वे उसे जमानत देने से इनकार करने के आधार भी नहीं हो सकते हैं। उत्तरवादी निश्चित रूप से गलत है जब वह कहता है कि क्योंकि



आवेदक अपने जवाब में टालमटोल कर रहा था, क्योंकि वह जांच के साथ सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसे सही ढंग से गिरफ्तार किया गया था और अब उसे हिरासत में रखा जाना चाहिए। यह प्रस्ताव नहीं हो सकता कि केवल तब जब एक आरोपी जांच एजेंसी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उस तरीके से देता है जिस तरीके से जांच एजेंसी चाहती है कि आरोपी उत्तर दे, तो इसका मतलब होगा कि आरोपी जांच के साथ सहयोग कर रहा है। इसके अलावा, उत्तरवादी टालमटोल वाले जवाब का हवाला देकर गिरफ्तारी और निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकता है।

25. हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत मूल सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए आरोपी बनाए जाने पर स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

इस न्यायालय ने यह माना है कि ऐसी सुरक्षा केवल उस साक्ष्य के संबंध में उपलब्ध नहीं है जो अदालत में विचारण के दौरान दिया जा सकता है, बल्कि यह पिछले चरण में भी उपलब्ध है यदि आरोपी के खिलाफ एक औपचारिक आरोप लगाया गया है जो सामान्य रूप से उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का परिणाम हो सकता है। इस प्रकार, यह सुरक्षा उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके खिलाफ एक औपचारिक आरोप लगाया गया है, हालांकि वास्तविक विचारण शुरू नहीं हुआ हो और यदि ऐसा आरोप किसी अपराध के कमीशन से संबंधित है जो सामान्य रूप से मुकदमा चलाने का परिणाम हो सकता है। एक आरोपी को चुप रहने का अधिकार है; उसे स्वयं के खिलाफ आत्म-अभियोगपूर्ण बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आरोपी की चुप्पी से कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यदि यह स्थिति है, तो आवेदक की गिरफ्तारी के लिए दिए गए आधार पूरी तरह से असंगत होंगे। ऐसे आधारों पर, आवेदक को सीबीआई मामले में आगे हिरासत में रखना न्याय का उपहास होगा, खासकर जब उसे पहले ही PMLA के अधिक सख्त प्रावधानों के तहत एक ही आरोपों पर जमानत प्रदान की जा चुकी है।"

26. इसके अलावा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका का उत्तर मनीष सिसोदिया के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले ही निम्नलिखित तरीके से दिया जा चुका है: 57. जहां तक साक्ष्यों से छेड़छाड़



की संभावना के बारे में विद्वान एएसजी द्वारा दी गई आशंका का सवाल है, यह ध्यान देने योग्य है कि यह मामला काफी हद तक दस्तावेजी साक्ष्यों पर निर्भर करता है, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने पहले ही जब्त कर लिया है। ऐसे में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। जहां तक गवाहों को प्रभावित करने के संबंध में चिंता का सवाल है, अपीलकर्ता पर कड़ी शर्तें लगाकर उक्त चिंता का समाधान किया जा सकता है।

10. इसलिए, यह मानते हुए कि यह कानूनी रूप से वैध है, गिरफ्तारी का समय, इसका पंजीकरण सब कुछ संदेहास्पद हो जाता है। आवेदक को ईओडब्ल्यू द्वारा तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने ECIR को रद्द किया, उसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया जब ईओडब्ल्यू में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। यह समय इस मानसिकता के साथ कि आरोपी को बाहर नहीं आने देना चाहिए, निंदनीय है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के इस कथन पर अपना भरोसा जताया कि एक शिकायत के आधार पर आगे की जांच के लिए आधार नहीं मिल सकता है।

11. आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक एक मात्र कर्मचारी है जो अपने नियोक्ता के निर्देशों पर कार्य कर रहा था और उसके खिलाफ कोई आपराधिक इरादे का सबूत नहीं है। आवेदक गलत धन का लाभार्थी नहीं है और उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। वह केवल कार्यालय प्रभारी था और मंत्रालयीन और लिपिकीय कार्य कर रहा था और उसे किसी भी अवैध गतिविधि की कोई जानकारी नहीं थी। होलोग्राम कंपनी के दायित्व को पूरा करने के लिए आपूर्ति और निर्माण के लिए भेजे जा रहे थे। इसलिए आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने \*\*अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 SCC 273\*\* के मामले में यह दिशानिर्देश दिया है कि गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए और आरोपी को सूचित किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा लिए गए आपराधिक बयान अमान्य हैं और उनका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है और जबरदस्ती या दबाव में लिए गए बयान अमान्य हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने



**\*\*हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) Supp.(1) SCC 335\*\*** के मामले में माना है। इसके अलावा, **\*\*भारत सरकार बनाम प्रफुल्ल कुमार समल (1979) 3 SCC 4\*\*** और **\*\*परमहंस जादव बनाम उड़ीसा राज्य (1991) 2 SCC 48\*\*** के मामलों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें यह माना गया है कि केवल संगति या उपस्थिति सामान्य इरादे या साजिश को साबित नहीं करती है। अभियोजन को एक अवैध कार्य करने के लिए पूर्व समझौते के अस्तित्व को साबित करना होगा, जो वर्तमान मामले में नहीं है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **\*\*वी. सेन्थिल बालाजी बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 (O) AIJEL-SC 74084\*\*** के मामले में दिए गए निर्णय पर अपना भरोसा जताया है, जिसमें पैरा 13 में यह कहा गया है:

"13. हमने ध्यानपूर्वक दलीलों पर विचार किया है। ED द्वारा आवेदक के खिलाफ आपराधिक सामग्री दिखाने के लिए मुख्य दस्तावेज़ जो पेन ड्राइव का हिस्सा है, जिसे राज्य पुलिस द्वारा आवेदक के परिसर से अनुसूचित अपराधों के संबंध में जब्त किया गया था। अनुसूचित अपराधों से संबंधित संबंधित अदालत ने जब्त किए गए पेन ड्राइव में सॉफ्ट फाइलों का मुद्रित संस्करण प्रदान किया है। इस स्तर पर, सॉफ्ट फाइलों की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। आवेदक के बैंक खाते में 1,34 करोड़ रुपये की नकद जमा दिखाने के लिए प्राथमिक सामग्री भी है। इस स्तर पर, आवेदक की ओर से यह दलील कि एमएलए के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक और कृषि आय के रूप में प्राप्त आय को जमा किया गया था, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदक की नकद आय के अस्तित्व को दिखाने के लिए कोई प्राथमिक सबूत नहीं है। इसलिए इस स्तर पर, यह मानना बहुत मुश्किल होगा कि PMLA की धारा 44 (1)(ब) के तहत दायर शिकायत और उसमें निर्भर सामग्री के खिलाफ आवेदक के खिलाफ कोई प्राथमिक मामला नहीं है।"

12. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि सह-आरोपी, जो कि मुख्य आरोपी है, को पहले ही इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है और आवेदक भी उसी आधार पर खड़ा है, इसलिए समानता के आधार पर, उसे जमानत प्रदान की जा सकती है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल नहीं है और अपराध में आवेदक की कोई



सीधी भागीदारी नहीं है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है और इसलिए, उसे भागने का जोखिम नहीं है। यह तर्क दिया गया कि आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या विचारण के चरण में उपलब्ध नहीं होने की कोई संभावना नहीं है, हालांकि सख्त शर्तें लगाई जा सकती हैं। आवेदक अपराध की आय का लाभार्थी नहीं है। अंत में, यह तर्क दिया गया है कि आवेदक की भूमिका होलोग्राम के वितरण को समन्वित करने तक सीमित है और यहां तक कि अभियोजन के मामले को ध्यान में रखते हुए भी यह कहा जा सकता है कि आवेदक का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा या ज्ञान नहीं था, जैसा कि उत्तरवादी द्वारा आरोप लगाया गया है। आवेदक ने पूरी जांच में सहयोग किया है और आवेदक का मामला मुख्य आरोपी के समान है, जिसे जमानत प्रदान की गई है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के \*\*कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन (2004)\*\* और \*\*संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012)\*\* के निर्णय पर जोर दिया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। आवेदक का कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और न्याय से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आपराधिक अदालतों को विचारण या सजा के खिलाफ अपील के दौरान आरोपी को जमानत देने के लिए विवेकाधीन अधिकार प्रदान करते हैं, चूंकि यह अधिकार विवेकाधीन है, इसे एक व्यक्ति के मूल्यवान स्वतंत्रता के अधिकार और सामान्य रूप से समाज के हित के बीच संतुलन बनाते हुए बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि ऐसी शक्ति को मान्यता दी जाती है, तो यह अराजक स्थिति पैदा कर सकती है और एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है। \*\*कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन (2005) 2 SCC 42\*\* में, यह माना गया है कि:

"18. यह स्थापित कानून है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक संवैधानिक गारंटी है। हालांकि, अनुच्छेद 21 जो उपर्युक्त अधिकार की गारंटी देता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से



व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वंचन की भी परिकल्पना करता है। इस देश के आपराधिक कानूनों के तहत, एक व्यक्ति जो गैर-जमानती अपराधों के लिए आरोपी है, विचारण लंबित होने के दौरान हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि उसे कानून के अनुसार जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है। ऐसी हिरासत को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जा सकता है क्योंकि यह कानून द्वारा अधिकृत है। लेकिन यहां तक कि गैर-जमानती अपराधों के आरोपी व्यक्ति भी जमानत के हकदार हैं यदि संबंधित अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन ने उसके खिलाफ प्राथमिक मामला स्थापित करने में विफल रहा है और/या यदि अदालत संतुष्ट है कि प्राथमिक मामले के अस्तित्व के बावजूद, तथ्यात्मक स्थितियों के कारण ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में, एक व्यक्ति जिसका जमानत आवेदन एक बार खारिज कर दिया गया है, वह तथ्यात्मक स्थिति में परिवर्तन होने पर जमानत के लिए बाद में आवेदन करने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसे मामलों में, यदि तब प्रचलित परिस्थितियों के कारण ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने की आवश्यकता होती है, तो अदालतें ऐसा कर सकती हैं।"

20. किसी उच्च मंच द्वारा दिए गए निर्णय, निस्संदेह, उसी मुद्दे पर अधीनस्थ मंचों पर बाध्यकारी होते हैं, यहां तक कि जमानत के मामलों में भी, जब तक कि तथ्यात्मक स्थिति में कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो जिसके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता हो। इसलिए, यद्यपि ऐसे मामलों में बाद में जमानत आवेदन दाखिल करने की गुंजाइश है जहां पहले के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, ऐसा तब भी किया जा सकता है जब तथ्यात्मक स्थिति या कानून में कोई ऐसा परिवर्तन हो जिसके लिए पहले के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो या जहां पहले का निष्कर्ष अप्रचलित हो गया हो। यह वह सीमित क्षेत्र है जिसमें एक अभियुक्त जिसे पहले जमानत देने से इनकार किया गया हो, बाद में आवेदन कर सकता है। इसलिए, हम अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को दी गई गारंटी के मद्देनजर, पीड़ित व्यक्ति के लिए लगातार जमानत आवेदन करना खुला



है, भले ही देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित पहले से ही अदालतों द्वारा खारिज किए गए आधार पर हो।

13. इसके अलावा, \*\*संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012) 1 SCC 40\*\* के मामले में यह माना गया है कि:

"10) श्री हरेन पी. रावल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अपने जवाब में यह प्रस्तुत करेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे इस प्रकार के हैं कि देश का आर्थिक ढांचा दांव पर लगा हुआ है। इसके अलावा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यह कहेंगे कि सजा की मात्रा किसी अपराध के परिमाण का एकमात्र निर्धारक कारक नहीं हो सकती है। वे कहेंगे कि जमानत देने के लिए प्रासंगिक विचारों में से एक समाज के हित के विपरीत आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और अदालत को पूर्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। श्री रावल आगे यह तर्क देंगे कि बदलती परिस्थितियों और परिदृश्य में, यह समाज के हित में था कि अदालत अपीलकर्ताओं को जमानत देने से इनकार करे। श्री रावल आगे यह तर्क देंगे कि इस न्यायालय के लिए निरंतरता आदर्श है और इस बात का कोई कारण या परिस्थिति में परिवर्तन नहीं है कि इस न्यायालय को 20 जून 2011 के आदेश से अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें उसी मामले में कुछ सह-आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया गया था। श्री रावल आगे यह कहेंगे कि इन मामलों में जांच की निगरानी इस न्यायालय द्वारा की जा रही है और विचारण दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ रहा है और अभियोजन एजेंसी द्वारा विचारण को पूरा करने में कोई देरी नहीं हुई है। इसके अलावा, वे यह प्रस्तुत करेंगे कि अपीलकर्ताओं द्वारा जांच में सहयोग करना, जमानत देने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि उनसे कानून द्वारा प्रदान किए गए जांच में सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है। वे आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने का परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई उचित आशंका है, और क्या कुछ गवाहों को खतरा है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं करने के लिए अब और अधिक कारण हैं, क्योंकि उन्हें अब गवाहों की पहचान का ज्ञान हो गया है, जो आरोपी के



कर्मचारी हैं, और यह आशंका है कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यह कहेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 में "प्रतीत होता है" शब्द का उपयोग किया गया है, और इसलिए, अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि धारा 87 के तहत तलब किए गए व्यक्ति के संबंध में विचारण न्यायाधीश की शक्ति धारा 88 द्वारा नियंत्रित होती है, गलत है। श्री रावल ने संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन और न्यायमूर्ति मलिमथ द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है, जिस पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी हवाला दिया है, और उन पर निर्णय के दौरान विचार किया जाएगा। बेंच के एक प्रश्न पर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यह प्रस्तुत करेंगे कि उनकी राय में, सभी भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए जो देश के आर्थिक ढांचे के लिए खतरा पैदा करते हैं, और संतुलन सार्वजनिक हित के पक्ष में झुकना चाहिए।"

14. जमानत आवेदनों में, आमतौर पर, यह सबसे पहले से ही निर्धारित किया गया है कि जमानत का उद्देश्य आरोपी व्यक्ति को उसके विचारण में उपस्थित होने के लिए उचित राशि की जमानत सुरक्षित करना है। जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक। स्वतंत्रता का वंचन एक दंड माना जाना चाहिए, जब तक कि यह आवश्यक न हो कि आरोपी व्यक्ति विचारण में उपस्थित होगा जब उसे बुलाया जाएगा। अदालतों को इस सिद्धांत के प्रति मौखिक सम्मान से अधिक देना चाहिए कि दंड सजा के बाद शुरू होता है, और यह कि हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे उचित रूप से आजमाया नहीं जाता और दोषी नहीं पाया जाता है। सबसे पहले से ही, यह मान्यता दी गई थी कि विचारण पूरा होने तक हिरासत में रखना बहुत बड़ी कठिनाई का कारण हो सकता है। समय-समय पर, आवश्यकता यह मांग करती है कि कुछ अदंडित व्यक्तियों को विचारण लंबित होने के दौरान हिरासत में रखा जाए ताकि उनकी विचारण में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, लेकिन ऐसे मामलों में, 'आवश्यकता' परिचालन परीक्षण है। इस देश में, यह संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के काफी विपरीत



होगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में दंडित किया जाए, जिस पर उसे दोषी नहीं ठहराया गया है या किसी भी परिस्थिति में, उसकी स्वतंत्रता को केवल इस विश्वास पर छोड़ा जाए कि यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, तो वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा, सबसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। निवारण के प्रश्न के अलावा, जमानत से इनकार करने का उद्देश्य होने के अलावा, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि सजा से पहले किसी भी कारावास में एक महत्वपूर्ण दंडात्मक सामग्री होती है और यह किसी भी अदालत के लिए अनुचित होगा कि वह पूर्व आचरण की अस्वीकृति के संकेत के रूप में जमानत से इनकार करे, चाहे आरोपी को इसके लिए दोषी ठहराया गया हो या नहीं या किसी अदंडित व्यक्ति को जेल का स्वाद देने के लिए जमानत से इनकार करे।"

15) इस मामले में, जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ "आरोप की ओर इशारा करने वाली उंगली" 'आरोप की गंभीरता' है। आरोप लगाए गए अपराध आर्थिक अपराध हैं जिसके कारण राज्य के खजाने को नुकसान हुआ है। हालांकि, वे यह दावा करते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है, उन्होंने आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है। हमारे विचार में, आरोप की गंभीरता निस्संदेह जमानत आवेदनों पर विचार करते समय प्रासंगिक विचारों में से एक है, लेकिन यह एकमात्र परीक्षण या कारक नहीं है: दूसरा कारक जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है सजा जो विचारण और सजा के बाद लगाई जा सकती है, भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दोनों के तहत। अन्यथा, यदि पूर्व एकमात्र परीक्षण है, तो हम संवैधानिक अधिकारों को संतुलित नहीं कर रहे होंगे बल्कि "न्याय के पैमाने को पुनः अशांकन कर रहे होंगे।" दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आपराधिक अदालतों को विचारण या सजा के खिलाफ अपील के दौरान आरोपी को जमानत देने के लिए विवेकाधीन अधिकार प्रदान करते हैं, चूंकि यह अधिकार विवेकाधीन है, इसे एक व्यक्ति के मूल्यवान स्वतंत्रता के अधिकार और सामान्य रूप से समाज के हित के बीच संतुलन बनाते हुए बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, विद्वान



जिला न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई तर्क, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, हमारी राय में, हमारी कानून प्रणाली के पूरे आधार और जमानत प्रणाली के सामान्य नियम का इनकार है। यह इस आवश्यकता के प्रति सम्मान को पार कर जाता है कि एक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक कि उसे दोषी नहीं ठहराया जाता है। यदि ऐसी शक्ति को मान्यता दी जाती है, तो यह अराजक स्थिति पैदा कर सकती है और एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है। इस न्यायालय ने \*\*कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन (2005) 2 SCC 42\*\* में यह माना है कि "इस देश के आपराधिक कानूनों के तहत, एक व्यक्ति जो गैर-जमानती अपराधों के लिए आरोपी है, विचारण लंबित होने के दौरान हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि उसे कानून के अनुसार जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है। ऐसी हिरासत को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जा सकता है क्योंकि यह कानून द्वारा अधिकृत है। लेकिन यहां तक कि गैर-जमानती अपराधों के आरोपी व्यक्ति भी जमानत के हकदार हैं यदि संबंधित अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन ने उसके खिलाफ प्राथमिक मामला स्थापित करने में विफल रहा है और/या यदि अदालत संतुष्ट है कि प्राथमिक मामले के अस्तित्व के बावजूद, तथ्यात्मक स्थितियों के कारण ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने की आवश्यकता है।"

14. बार-बार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जमानत नियम हैं और जेल में भेजना अपवाद है। यह भी माना गया है कि जमानत से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है।

15. राज्य की ओर से डॉ. सौरभ पांडेय, उप महाधिवक्ता का तर्क है कि प्रवर्तन निदेशालय से 11.07.2023 को प्राप्त संचार के आधार पर और उचित सत्यापन के बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 तथा IPC की धारा 420, 467, 471 और 120-बी के तहत आवेदक के खिलाफ एक प्राथमिक संज्ञेय अपराध बनाया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपराध संख्या 04/2023 के तहत पंजीकृत किया गया। राज्य की ओर से अधिवक्ता ने तर्क किया है कि एक आपराधिक सिंडिकेट जिसमें उच्च स्तरीय



राज्य सरकार के अधिकारी, निजी व्यक्ति और राज्य सरकार के राजनीतिक कार्यकारी शामिल थे, छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहे थे और राज्य विभागों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अवैध रिश्तों तक कर रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की बिक्री उनके अवैध आय का एक प्रमुख स्रोत था, जिसे निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया गया है:

i) भाग -अ: छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पर लेखांकन से शराब

आपूर्तिकर्ताओं से लिया गया अवैध कमीशन ।

ii) भाग -ब : राज्य संचालित दुकानों से ऑफ द रिकॉर्ड

अलेखांकित देशी शराब की बिक्री जो आसवक, होलोग्राम

निर्माता, बोतल निर्माता, परिवहनकर्ता, मानव संसाधन

प्रबंधन और जिला आबकारी अधिकारियों की सक्रिय

भागीदारी से की गई थी।

भाग -स: छत्तीसगढ़ राज्य में आसवकों को काम करने की

अनुमति देने के लिए दिया गया वार्षिक कमीशन।

16. ईओडब्ल्यू ने आयकर विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी और डेटा का विश्लेषण किया है और उक्त दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर, यह स्थापित किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग में अवैध कमीशन कमाने के लिए सिंडिकेट द्वारा एक साजिश को अंजाम दिया गया था और तदनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2024 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। जांच के लिए, शराब को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात् देशी शराब और भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL)। देशी शराब छत्तीसगढ़ राज्य में तीन आसवनशालाओं के माध्यम से उत्पादित की जाती है:

i) M/s. छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड,

ii) M/s. भाटिया वाइन्स एंड मर्चेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।

iii) M/s. वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड।



जांच में यह सामने आया है कि 2019 से आबकारी विभाग में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आबकारी विभाग शराब की आपूर्ति को विनियमित करने, उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब सुनिश्चित करने, नशा संबंधी त्रासदियों को रोकने और राज्य के लिए आबकारी अर्जित करने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन श्री अनवर ढेबर और श्री अनील टुटेजा के नेतृत्व में आपराधिक सिंडिकेट ने व्यवस्थित रूप से शराब नीति को अपनी मनमानी के अनुसार बदल दिया और अपने लिए अधिकतम व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी नीति को 2017 में संशोधित किया गया था और CSMCL फरवरी, 2017 में इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि यह अपने स्टोर के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रूप से शराब खुदरा बेचेगी। CSMCL को वास्तविक शराब प्रदान करने, अवैध शराब की बिक्री को रोकने, MRP पर शराब प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ स्थापित किया गया था। इसने निर्माताओं से सीधे शराब/बीयर/वाइन/देशी शराब खरीदने के बाद अपने स्वयं के स्टोर स्थापित किए।

17. इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित तथ्यों और साक्ष्य से, प्रारंभिक जांच के बाद, ईओडब्ल्यू द्वारा 27.09.2024 को संबंधित अदालत में प्रारंभिक आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि वर्तमान आवेदक जो प्रिज्म होलोग्राफी एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में प्रभारी के रूप में कार्यरत था, आबकारी घोटाले में नकली होलोग्राम के परिवहन और मुद्रण में शामिल था। आवेदक अपने नियोक्ता विधु गुप्ता से सभी तीन आसवकों, अर्थात् CG डिस्टिलरीज लिमिटेड, भाटिया वाइन और वेलकम डिस्टिलरीज, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत हैं, को नकली होलोग्राम की सुविधा प्रदान करने में मुख्य व्यक्ति है, जिसका मुख्यालय नोएडा, यूपी में है, अमित सिंह के समन्वय में है। अमित सिंह प्रकाश शर्मा @ छोदू को आवेदक की मदद करने के लिए भेजता था ताकि नकली होलोग्राम एकत्र और वितरित किया जा सके। अक्टूबर 2013 से दिसंबर 2019 तक आवेदक को रायपुर में नकली होलोग्राम प्राप्त हुआ और इसे विभिन्न



आसवनशालाओं को वितरित किया गया और नकली होलोग्राम को ईओडब्ल्यू द्वारा धनेली, रायपुर में अनुराग द्विवेदी के बॉटलिंग प्लांट से जब्त किया गया।

18. यह भी उल्लेख किया गया है कि बॉटलिंग इकाई के भूमि मालिक अनवर डेबर हैं। बाद में आवेदक ने दीपक दुआरी के साथ समन्वय किया ताकि नकली होलोग्राम वितरित किए जा सकें जो वर्तमान आवेदक की देखरेख में मुद्रित किए गए थे और आसवनशालाओं को आपूर्ति की गई थी। जांच के दौरान, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आवेदक का ज्ञापन बयान दर्ज किया गया, जिसमें नोएडा से रायपुर को नकली होलोग्राम की आपूर्ति के विवरण वाले परिवहन परमिट और चालान जब्त किए गए थे।

19. राज्य की ओर से डॉ. पांडेय, अधिवक्ता ने तर्क किया है कि कई निर्णयों में, जमानत आवेदन पर विचार करते समय, अदालत को तीन कारकों पर विचार करना चाहिए, अर्थात् i) भागने का जोखिम या न्याय से भागने की संभावना; ii) साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना और iii) गवाहों को प्रभावित करने की संभावना। वर्तमान मामले में आवेदक एक सिंडिकेट का हिस्सा था और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध शराब की बिक्री में शामिल था और राज्य के खजाने में भारी राजस्व की हानि हुई है और इस प्रकार, यह दर्शाता है कि आवेदक द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना है और उपर्युक्त परिस्थितियों के प्रकाश में, आवेदक को जांच के दौरान जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

20. संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं, रिकॉर्ड और संलग्न दस्तावेजों को अत्यंत सावधानी के साथ परिशीलन किया गया।

21. इस मामले में, आवेदक और अन्य सह-आरोपियों द्वारा एक संगठित अपराध किया जाने का आरोप लगाया गया है, जिनमें से कुछ उच्च पदों पर आसीन हैं, जैसे कि IAS और ITS अधिकारी हैं। वर्तमान मामले में, प्रवर्तन निदेशालय से सूचना प्राप्त करने के बाद, ईओडब्ल्यू ने उपर्युक्त अपराधों के कमीशन के लिए प्राथमिक संज्ञेय अपराध दर्ज



किया है और आवेदक के खिलाफ अपराध संख्या 04/2024 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो 15 फरवरी 2024 से हिरासत में है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 तथा IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए है। अभियोजन का मामला यह है कि एक आपराधिक सिंडिकेट जिसमें उच्च स्तरीय राज्य सरकार के अधिकारी, निजी व्यक्ति और राज्य सरकार के राजनीतिक कार्यकारी शामिल थे, छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहे थे और राज्य विभागों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अवैध रिश्तों के माध्यम से लाभ कर रहे थे, जिसमें शराब की बिक्री उनके अवैध आय का एक प्रमुख स्रोत था। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि 2019 से छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आबकारी विभाग शराब की आपूर्ति को विनियमित करने, उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब सुनिश्चित करने, नशा संबंधी त्रासदियों को रोकने और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन आपराधिक सिंडिकेट ने नीति को अपनी मनमानी के अनुसार बदल दिया और अपने लिए अधिकतम व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया और 2019-20 से 2022-23 तक के वित्तीय वर्ष में राज्य के खजाने को कुल 1660,41,00,056/- रुपये की हानि हुई। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ कोई प्राथमिक अपराध नहीं बनता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद, जो यह दर्शाता है कि आवेदक का अपराध में शामिल होना और आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि सह-आरोपी, जो कि मुख्य आरोपी है, को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई है और वर्तमान आवेदक भी उसी आधार पर उपस्थित है, इसलिए समानता के आधार पर, उसे जमानत प्रदान की जा सकती है। इस तर्क के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सह-आरोपी को मुख्य रूप से चिकित्सा आधार पर जमानत प्रदान की गई थी, जो गंभीर चिकित्सा मुद्दों और उसकी निरंतर चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता को देखते हुए थी और इस प्रकार, वर्तमान



आवेदक के संबंध में कोई गंभीर चिकित्सा मुद्दा नहीं है और इसलिए , वह समानता के आधार पर जमानत की मांग नहीं कर सकता है।

22. इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , और अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका, जिस तरीके से उस पर अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है और इस प्रकार वह एक सिंडिकेट का हिस्सा था और नकली होलोग्राम प्रदान करने में सहायता करके अवैध आय में शामिल था, और आरोप और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए आवेदक पर आरोप लगाया गया है, जो अत्यंत गंभीर है, इसलिए इस न्यायालय की राय में, उपर्युक्त कारणों से वर्तमान आवेदक को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश देना उचित नहीं है।

23. तदनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ('BNSS') की धारा 483 के तहत आवेदक द्वारा की गई जमानत आवेदन को **निरस्त** किया जाता है।

एसडी/-

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।